



RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 17 अंक : 21

प्रति सोमवार, 12 अक्टूबर 2026

मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

खाद्यमंत्री गोविंद सिंह राजपूत की भ्रष्टाचारी राशन वितरण व्यवस्था का हुआ पर्दाफाश

महीने में दो बार राशन वितरण व्यवस्था लागू कर गरीबों के हिस्से का राशन चट कर रहे राजपूत



अंत्योदय और गरीब कल्याण का मंत्र लेकर कार्य कर रही मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार के मंसूबों से पर्दाफाश हो गया है। दरअसल से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कैबिनेट के सदस्य और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किस तरह से गरीबों को वितरित किये जाने वाले राशन के साथ बंदरवाट किया है उसका खुलासा हो गया है। अपने विधानसभा क्षेत्र से लेकर राजधानी भोपाल और तमाम जिलों में गोविंद सिंह राजपूत ने गरीब कल्याण के लिए दिये जाने वाले राशन में भी भ्रष्टाचार का जाल बिछा दिया। यही नहीं राजपूत ने इस बार कोई छोटा-मोटा जाल नहीं बिछाया बल्कि यह जाल इतना बड़ा है कि इसकी चपेट में राशन हितग्राही बड़ी ही आसानी से लपेटे में आ गये। दरअसल गोविंद सिंह राजपूत ने बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से महीने में एक बार मिलने वाले राशन का बंटवारा महीने में दो बार करने



की योजना बनाई। पिछले कई महीनों से यह सुविधा प्रदेशभर की राशन वितरण की दुकानों पर लागू कर दी गई और इससे आमजनता को राशन लेने के लिए अब दो-दो बार लाइन में लगना होता है। यही नहीं राशन की दुकान के संचालक पहली बार में ही गरीब व्यक्ति को मिलने वाले राशन की पच्ची निकलवा लेते हैं लेकिन उन्हें राशन दिया सिर्फ आधा ही दिया जाता है। आधा राशन उन्हें दोबारा लाइन में लगकर फिर से लेना पड़ता है।

मुख्यमंत्री से बगैर पूछे ले लिया वितरण व्यवस्था में बदलाव का फैसला

गोविंद सिंह राजपूत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल के दौरान एक अलग ही तेवर में दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ समय से हाशिये पर रहे राजपूत ने भ्रष्टाचार का ऐसा जाल बिछाया कि मुख्यमंत्री भी बगैर फंसे इसमें रह नहीं गये। मुख्यमंत्री को आधी-अधूरी जानकारी देकर उन्होंने मौखिक रूप से ही हमी भरवाकर राशन वितरण की व्यवस्था को बदल दिया। (शेष पेज 2 पर)

जंगल की महक से बाजार की पहचान तक पहुंचा महुआ, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में जनजातीय आजीविका को मिल रही नई राह

-विजया पाठक
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग, जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तीकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास अब जमीन पर नए बदलावों के रूप में दिखाई देने लगे हैं। जशपुर के जंगलों में सहज रूप से उपलब्ध महुआ इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण बनकर उभर रहा है। कभी पारंपरिक वन उपज और सीमित उपयोग तक पहचाना जाने वाला महुआ अब आधुनिक खाद्य उत्पादों, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, आकर्षक पैकेजिंग और बाजारोन्मुखी नवाचार के माध्यम से नई पहचान हासिल कर रहा



है। यह बदलाव मुख्यमंत्री साय की उस कार्यशैली को रेखांकित करता है, जिसमें स्थानीय संभावनाओं को पहचानकर उन्हें आजीविका, उद्यमिता और आर्थिक विकास से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जशपुर में महुआ को केवल जंगल से एकत्रित की जाने वाली उपज के रूप में देखने के बजाय उसे स्थानीय अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जशपुर और जय जंगल जैसी पहलों के माध्यम से महुआ के संग्रहण, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और विपणन को नई दिशा मिल रही है। इससे जनजातीय परिवारों और महिला स्वसहायता समूहों के लिए आय के नए अवसर तैयार करने की संभावनाएं मजबूत हो रही हैं।

इंडिया इंस्टिट्यूट फेयर में दिल्ली जशपुर के महुआ की नई पहचान

रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 18 से 20 सितंबर तक आयोजित 14वें इंडिया इंस्टिट्यूट फेयर में जशपुर के महुआ उत्पादों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मेले में जशपुर और जय जंगल के स्टॉल पर प्रदर्शित उत्पादों ने यह दिखाया कि स्थानीय वन उपज को आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता और बाजार की जरूरतों के अनुरूप विकसित करके व्यापक उपभोक्ता वर्ग तक पहुंचाया जा सकता है। मेले के हॉल नंबर-3 में स्टॉल नंबर 4 और 5 पर महुआ नेक्टर, महुआ नेक्टर गोल्ड, वन्यप्राश, महुआ एनर्जी पाचक, महुआ टी, महुआ आधारित कुकीज, रागी-महुआ उत्पाद, महुआ लड्डू और फूड-ग्रैड महुआ फूल सहित अनेक उत्पाद प्रदर्शित किए गए। (शेष पेज 2 पर)

जंगल की महक से बाजार की पहचान तक पहुंचा महुआ, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन में जनजातीय आजीविका को मिल रही नई राह

(पेज 1 का शेष)

इन उत्पादों की विविधता, आधुनिक प्रस्तुति और आकर्षक पैकेजिंग ने आगंतुकों को महुआ के नए स्वरूप से परिचित कराया। लोगों ने उत्पादों की जानकारी ली और उनके स्वाद, गुणवत्ता तथा प्रस्तुति की सराहना की। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि स्थानीय संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए, तो वे केवल परंपरा का हिस्सा बनकर नहीं रहते, बल्कि आधुनिक बाजार में भी अपनी जगह बना सकते हैं। इससे वन उपज के आर्थिक महत्व को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन की संभावनाओं को विस्तार देने का रास्ता खुलता है।

सुशासन का उद्देश्य स्थानीय संसाधनों को बनाना आजीविका का आधार

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कार्यशैली में स्थानीय जरूरतों, उपलब्ध संसाधनों और जनजातीय समुदायों की आर्थिक संभावनाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्व दिखाई देता है। जशपुर में महुआ को नया स्वरूप देने की पहल इसी सोच से जुड़ी है। इसका उद्देश्य केवल नए उत्पाद तैयार करना नहीं, बल्कि जंगल से बाजार तक की प्रक्रिया में स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आर्थिक अवसरों को मजबूत करना भी है। जशपुर की प्राकृतिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय समुदायों, महिला समूहों, उत्पादक संस्थाओं और तकनीकी संस्थानों के सहयोग से काम किया जा रहा है। महुआ सहित अन्य स्थानीय वन उपज के संग्रहण, प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और बाजार तक पहुंच बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सुशासन का वास्तविक महत्व तब सामने आता है, जब प्रशासनिक प्रयास लोगों के जीवन में उपयोगी अवसर पैदा करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग, तकनीकी सहयोग, उत्पादों की गुणवत्ता

में सुधार और बाजार से जुड़ाव इसी प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलु हैं। जशपुर में महुआ के क्षेत्र में हो रहे प्रयास इस दिशा में संभावनाएं प्रस्तुत करते हैं। इससे स्थानीय स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पेड़ से बाजार तक विकसित हो रही मूल्य संवर्धन की शृंखला

महुआ को बाजार में नई पहचान दिलाने के लिए केवल उत्पाद तैयार करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संग्रहण से लेकर अंतिम उत्पाद के विपणन तक प्रत्येक चरण को बेहतर बनाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से स्वच्छ और फूड-ग्रेड संग्रहण, डिहाइड्रेशन, वैज्ञानिक प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान, उत्पाद विकास और पैकेजिंग जैसे पहलुओं पर काम किया जा रहा है। जिला प्रशासन जशपुर के सहयोग से संचालित महुआ सेंटर ऑफ एक्सर्सेस और 'महुआ कोष' में महुआ के खाद्य उपयोग, नए उत्पादों के विकास, फूड-ग्रेड संग्रहण तथा प्रसंस्करण तकनीकों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और प्रयोग किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का लक्ष्य महुआ की गुणवत्ता और बाजार मूल्य बढ़ाने के साथ उसके उपयोग की संभावनाओं का विस्तार करना है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वन उपज का मूल्य केवल उसके संग्रहण तक सीमित न रहे। जब स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, पैकेजिंग और उत्पाद विकास की गतिविधियां आगे बढ़ती हैं, तो मूल्य श्रृंखला में रोजगार और उद्यमिता के अतिरिक्त अवसर बन सकते हैं। इससे महुआ संग्रह करने वाले परिवारों, स्थानीय उत्पादकों और महिला स्वसहायता समूहों को लाभ पहुंचाने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं।

महिला भागीदारी और पारंपरिक ज्ञान को मिल रहा नया मंच

इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में जशपुर और

जय जंगल के स्टॉल का प्रतिनिधित्व जशपुर की अनेश्वरी भगत और गणपति बाई ने किया। उन्होंने आगंतुकों को महुआ आधारित उत्पादों की जानकारी देने के साथ उसके संग्रहण, फूड-ग्रेड बनाने की प्रक्रिया और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने के प्रयासों के बारे में बताया। यह भागीदारी स्थानीय महिलाओं के ज्ञान और अनुभव को व्यापक बाजार के सामने प्रस्तुत करने का अवसर भी है। महिला स्वसहायता समूहों और स्थानीय समुदायों को उत्पादन तथा विपणन की प्रक्रिया से जोड़ने की दिशा में ऐसे प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर कौशल विकास के नए रास्ते खुलने की संभावना है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने की यह दिशा जनजातीय क्षेत्रों की पारंपरिक संपदा को विकास के अवसर में बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। हालांकि, इन संभावनाओं को स्थायी परिणामों में बदलने के लिए निरंतर बाजार संपर्क, गुणवत्ता मानकों का पालन और उत्पादकों को उचित आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा।

अनुसंधान से महुआ के नए उपयोगों की संभावनाएं

महुआ के खाद्य उपयोग का विस्तार होने के साथ उसके पोषण संबंधी पहलुओं पर भी अनुसंधान की संभावनाएं सामने आ रही हैं। जय जंगल के निदेशक समर्थ जैन के अनुसार, कुछ ग्राहकों ने महुआ के सेवन के बाद आयरन और हीमोग्लोबिन से जुड़े सकारात्मक अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने इन अनुभवों की वैज्ञानिक जांच और महुआ में आयरन की मात्रा के साथ शरीर में उसके उपलब्धता तथा उपयोगिता के व्यवस्थित अध्ययन को अगला महत्वपूर्ण कदम बताया। इस संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान और

प्रमाणित निष्कर्ष आवश्यक हैं। महुआ के संभावित पोषण लाभों को लेकर किसी भी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसकी संरचना, पोषक तत्वों की उपलब्धता और शरीर पर प्रभाव का वैज्ञानिक मूल्यांकन जरूरी है। ऐसे अध्ययन भविष्य में महुआ के उपयोग और उत्पाद विकास की दिशा तय करने में सहायक हो सकते हैं।

जशपुर से व्यापक बाजार तक पहुंचने की उम्मीद

14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर में जशपुर के महुआ उत्पादों की प्रस्तुति स्थानीय संसाधनों को आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा सकती है। इसमें प्रशासनिक सहयोग, पारंपरिक ज्ञान, तकनीकी अनुसंधान, महिला भागीदारी और उद्यमिता का समन्वय दिखाई देता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में स्थानीय एवं जनजातीय उत्पादों के मूल्य संवर्धन पर केंद्रित ऐसे प्रयास जशपुर की प्राकृतिक संपदा को आर्थिक अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। महुआ की यह यात्रा बताती है कि विकास की संभावनाएं केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं हैं। स्थानीय संसाधनों की पहचान, उनकी गुणवत्ता में सुधार और बाजार से प्रभावी जुड़ाव के माध्यम से भी ग्रामीण और जनजातीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी जा सकती है। जशपुर का महुआ आज जंगल से निकलकर आधुनिक बाजार तक पहुंचने की राह पर है। यह पहल पारंपरिक वन उपज को नवाचार, प्रसंस्करण और उद्यमिता से जोड़ने के साथ जनजातीय परिवारों तथा महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करने की उम्मीद जगाती है। स्थानीय संसाधनों को सम्मान, तकनीक और बाजार से जोड़ने की यही सोच सुशासन को जनजीवन से जोड़ने और विकास को गांवों तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

हर महीने 15 से 20 करोड़ रुपये का राशन रसूखदारों और व्यापारियों को बेच रहे मंत्री राजपूत

(पेज 1 का शेष)

जबकि इसमें मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट की सिफारिश उपरांत ही व्यवस्था बदलने का अधिकार होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या राजपूत के पंख इतने निकलने लगे कि वे बिना कैबिनेट और मुख्यमंत्री की परमिशन के इतना बड़ा फैसला स्वतः ले सकें।

करोड़ों रुपये के राशन का बंदरवाट

मंत्री राजपूत द्वारा बनाई गई इस राशन वितरण व्यवस्था में करोड़ों रुपये का बंदरवाट होता है। सिर्फ राशन का बंदरवाट ही नहीं बल्कि बड़े बड़े अनाज साहूकारों को पीछे के रास्ते से मोटे रुपये के एवज में गरीबों के हिस्सों में आने वाला यह राशन बांट दिया जाता है। राजपूत द्वारा पिछले चार महीने से भी अधिक समय से इस खेल को खेला जा रहा है। राशन वितरण प्रणाली के इस खेल में राजपूत ने अब तक लगभग 65 करोड़ रुपये का घोटाला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को इस मामले पर तुरंत सज्जन लेते हुए इसकी जांच करवाते हुए राजपूत पर कड़ी कार्यवाही करना चाहिए।

कोयले की खदान में सिंधिया के हाथ काले

गरीब कल्याण के लिए वितरण किये जाने वाले अन्न वितरण के इस कार्य में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संरक्षण है। उनके इशारे पर ही राजपूत ने वितरण प्रणाली को बदलने

का प्रयास किया और वह अपने मंसूबों पर सफल भी हो गये। लेकिन जैसे-जैसे राजपूत के कारनामे आमजनता को समझ आने लगे तो लोगों ने इसका विरोध शुरू किया। आलाम यह हुआ कि राजपूत ने सागर जिले के सुरखी विधानसभा सीट से उठती इन आवाजों को यह तो पैसे का लालच देकर चुप कर दिया या फिर डरा-धमकाकर उन्हें आवाज उठाने से रोक दिया।

राजपूत की वितरण व्यवस्था को ऐसे समझे

दरअसल एक वर्ष पहले तक राशन की दुकान में प्रत्येक माह की 4 तरीख से 30 तरीख तक राशन दिया जाता था। ऐसे में हर व्यक्ति को एक बार में ही उनीके पात्रता अनुसार राशन दिया जाता। लेकिन मंत्री राजपूत ने इस व्यवस्था को बदलते हुए पर्याप्त अन्न उपलब्ध न होने का कहते हुए व्यवस्था को अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया। यानि कि 4 से 15 तक गेहूँ का वितरण और 16 से 30 तक चावल का वितरण। लेकिन प्रति व्यक्ति पात्रता अनुसार जो भी खाद्य उन्हें मिलना है उसकी पूर्ति व्यक्ति पात्रता अनुसार जो भी खाद्य उन्हें मिलना है उसकी पूर्ति व्यक्ति किसी काम के चलते अन्न लेने न पहुंचे तो उस माह का उसके हिस्से का अन्न राजपूत के वेयरहाउस में पहुंच जाता है और वहां से साहूकारों और अनाजमील मालिकों तक सीधे पहुंचा दिया जाता है जिसके बदले में उनसे मोटी रकम ली जाती है।

दूसरे राज्यों में नहीं है यह व्यवस्था

मध्यप्रदेश के अलावा दूसरे किसी भी राज्य में राशन वितरण प्रणाली पूर्ण की तरह संचालित है। सभी राज्यों में राशन की दुकानों पर पात्र व्यक्ति को एक बार में ही पर्याप्त राशन दिया जाता है और जिसके बाद उन्हें दोबारा आने की आवश्यकता नहीं होती।

05 करोड़ से अधिक लोगों को मिलता है राशन

खाद्य विभाग अनुसार मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लगभग 1.32 करोड़ राशन कार्ड परिवार और करीब 5.36 करोड़ से अधिक लाभार्थी) सरकारी राशन का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतने बड़ी संख्या में बंटने वाले राशन के साथ कैसे गोविंद सिंह राजपूत खिलवाड़ कर रहे हैं। जांच का विषय यह है कि इस पूरे खेल में मंत्री राजपूत और सिंधिया के अलावा कौन-कौन नेता और व्यापारी शामिल हैं सभी के नाम सामने आने चाहिए।

राजधानी का यह हाल तो अन्य स्थलों पर क्या

खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की इन कर्तूतों पर प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता ने आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि जब राशन वितरण व्यवस्था में इतना बड़ा खेल राजधानी भोपाल में उजागर हुआ है तो यह सोचने वाली बात है कि अन्य शहरों और जिलों में क्या दशा होगी।

वरिष्ठजनों का हुआ सम्मान

-बद्रीप्रसाद कौरव

उग्रत प्रवाह. गाडरवारा। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के तत्वावधान में ब्रह्माकुमारीज लक्ष्मी टाउनशिप, गाडरवारा में 1 अक्टूबर को "संगम गौरवपूर्ण वृद्ध अवस्था एवं सम्मानित जीवन" विषय पर वरिष्ठजनों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सायं 4:30 बजे प्रारंभ हुआ यह कार्यक्रम स्नेह, सम्मान, आध्यात्मिकता, संस्कार एवं उमंग से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ सदस्य एवं समाजसेवी अनूप जैन, पेंशनर समाज गाडरवारा के अध्यक्ष महेश नेमा, राम रोटी संस्थान से विशाल सिंह ठाकुर, समाजसेवी श्याम राठी एवं जी.एस. कौरव (कदम संस्था सदस्य) सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ब्रह्माकुमारीज गाडरवारा की प्रभारी ब्रह्माकुमारी उर्मिला दीदी जी, ब्रह्माकुमारी वंदना दीदी जी एवं ब्रह्माकुमारी अंजना दीदी जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों का संस्था की ओर से आत्मीय एवं गरिमामय सम्मान किया गया। वरिष्ठजनों को सम्मान पट्टा पहनाकर, बैज लगाकर एवं आध्यात्मिक साहित्य भेंट किया गया तथा प्रभु प्रसाद अर्पित कर उनका अभिनंदन किया गया। सम्मान प्राप्त कर वरिष्ठजनों के चेहरे पर खुशी और आत्मीयता की झलक दिखाई दी। उर्मिला दीदी जी ने वरिष्ठजनों को भी सदैव सकारात्मक सोच रखने, प्रसन्न रहने और अपने अनुभवों से परिवार एवं समाज को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि उम्र जीवन की यात्रा का एक पड़ाव है, जबकि मन में उमंग, उत्साह और सकारात्मकता बनाए रखकर जीवन को सदैव आनंदमय बनाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जारी की महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त 67.38 लाख से अधिक माताओं-बहनों के खातों में पहुंचे 632.40 करोड़

-शशि पांडे

उग्रत प्रवाह. रायपुर। छत्तीसगढ़

की लाखों माताओं-बहनों के आर्थिक स्वावलंबन, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को मजबूत कर रही महतारी वंदन योजना ने आज एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दुर्ग जिले में आयोजित कार्यक्रम में योजना की 32वीं किस्त जारी करते हुए प्रदेश की 67 लाख 38 हजार 217 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 632 करोड़ 40 लाख रुपये से अधिक की राशि अंतरित की। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के अंतर्गत माताओं-बहनों को अब तक दी गई आर्थिक सहायता की राशि 20,708 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि मातृशक्ति का सम्मान और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हमारी सरकार के लिए केवल एक योजना या कार्यक्रम नहीं, बल्कि सुशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। हमारा विश्वास है कि जब परिवार की महिला आर्थिक



रूप से सशक्त होती है, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा और पोषण से लेकर परिवार के स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े निर्णयों तक उसकी भागीदारी और मजबूत होती है। इसलिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से सरकार माताओं-बहनों के हाथों में आर्थिक सामर्थ्य देकर उन्हें अपने निर्णय

स्वयं लेने का आत्मविश्वास दे रही है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना इसी संकल्प का सशक्त उदाहरण है। प्रतिमाह मिलने वाली एक हजार रुपये की राशि लाखों महिलाओं के लिए अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने का भरोसेमंद आर्थिक आधार बनी है। कोई बहन इस राशि का उपयोग बच्चों की पढ़ाई में कर रही है, कोई पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में, तो कोई अपनी छोटी-छोटी बचत और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में इसका उपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि महतारी वंदन की राशि केवल बैंक खातों में पहुंचने वाली आर्थिक सहायता नहीं है। यह माताओं-बहनों के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन को नई शक्ति देने वाली राशि है। हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश की माताएं-बहनें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हों, बल्कि परिवार और समाज के निर्णयों में उनकी भागीदारी भी निरंतर बढ़े।

'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम

-अमित राय

उग्रत प्रवाह. हुगली। 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हुगली जिले के श्रीरामपुर में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व राष्ट्रीय स्वयं सेवक (आरएसएस) प्रचारक सुनील देवधर बतौर मुख्य अतिथि व प्रधान वक्ता उपस्थित हुए। उन्होंने वंदे मातरम् के महत्व, भारतीय संस्कृति, कृतज्ञता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना का प्रतीक है। भारतीय परंपरा में प्रकृति, धरती, नदियों और अन्य जीवनदायी तत्वों को सम्मान देने की परंपरा रही है। इसी संदर्भ में मातृभूमि को माता के रूप में देखने की भावना को भारतीय संस्कृति की विशेषता बताया गया। इसी भाव को व्यापक रूप देते हुए मातृभूमि के प्रति भी कर्तव्य और सम्मान की भावना विकसित करने का आह्वान किया गया। देवधर ने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक उदाहरणों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि भारतीय समाज में नारी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त रहा है।



उन्होंने सीता, द्रौपदी, अहिल्याबाई होलकर और सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं का उल्लेख करते हुए शिक्षा, नेतृत्व और सामाजिक योगदान में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित

किया। उन्होंने युवाओं को शिक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और शारीरिक क्षमता विकसित करने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि राष्ट्र की मजबूती केवल सरकार या संस्थाओं से नहीं,



बल्कि जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों से होती है। युवाओं से सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करने तथा समाज और देश से जुड़े विचारों को जिम्मेदारी के साथ

साझा करने की अपील भी की। भारतीय इतिहास और संस्कृति की चर्चा करते हुए उन्होंने शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस तथा अन्य ऐतिहासिक और सामाजिक व्यक्तित्वों का उल्लेख किया। उन्होंने भारतीय सभ्यता को प्राचीन और विविधतापूर्ण बताते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कुछ ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक घटनाओं से जुड़े अनेक दावे और आरोप का वर्णन करते हुए उन्होंने ऐसे दावों को समझते समय उनके ऐतिहासिक संदर्भ और प्रमाणों की स्वतंत्र रूप से जाँच करना को आवश्यक बताया। साथ ही कहा कि किसी भी समुदाय या समूह के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय तथ्यों और सैद्धांतिक मूल्यों के आधार पर विचार करना अधिक उचित है। सुनील देवधर ने सामाजिक भेदभाव और जातिवाद को हिन्दू समाज की कमजोरी बताते हुए सामाजिक समरसता का संदेश दिया। उन्होंने सभी वर्गों के लोगों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने और त्यागहारों तथा सामाजिक आयोजनों को एकता का माध्यम बनाने की अपील की।

सम्पादकीय संसद से सड़क तक मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है। जनता अपने मताधिकार के माध्यम से सरकार चुनती है और निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया की निष्पक्षता का संवैधानिक प्रहरी है। ऐसे में जब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग संसद से लेकर सड़क तक उठने लगे, तो यह केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव का विषय नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध कांग्रेस और विपक्षी दलों का विरोध इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूचियों में संशोधन को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है तथा इससे पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। इन आरोपों के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर से निर्वाचन आयोग के कार्यालय की ओर मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी सहित कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है।

यहां सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया आम नागरिक के मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त पारदर्शी है? मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियादी दस्तावेज है। इसमें किसी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल होना जितना गंभीर विषय है, उतना ही गंभीर किसी पात्र नागरिक का नाम हट जाना भी है। किसी व्यक्ति को मतदान से वंचित करना उसके संवैधानिक अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी को प्रभावित कर सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी केवल सूची को अद्यतन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि कोई वास्तविक मतदाता अनावश्यक कागजी कार्रवाई या प्रशासनिक त्रुटियों के कारण अपने अधिकार से वंचित न हो। दूसरी ओर,

मतदाता सूचियों का समय-समय पर पुनरीक्षण आवश्यक है। आयोग का तर्क है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से सूचियों को अधिक सटीक बनाया जा सकता है और उनमें मौजूद त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। इसलिए केवल विरोध के आधार पर किसी प्रशासनिक प्रक्रिया को अनुचित घोषित करना उचित नहीं होगा। लेकिन किसी प्रक्रिया का उद्देश्य अच्छा होने मात्र से उसके क्रियान्वयन पर उठने वाले सवाल समाप्त नहीं हो जाते। आयोग को स्पष्ट आंकड़ों, पारदर्शी नियमों और शिक्षावर्तों के समयबद्ध निस्तारण के माध्यम से जनता का विश्वास मजबूत करना चाहिए।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग के मामले में संवैधानिक प्रक्रिया को समझना भी जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त को साधारण राजनीतिक असहमति के आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता। उनके पद की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए संविधान में कठोर प्रक्रिया निर्धारित है। इसलिए राजनीतिक दलों को अपनी मांगों और आरोपों को प्रमाणों के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। संसद में बहस, तथ्यों की जांच और संवैधानिक प्रावधानों का पालन इस विवाद का उचित रास्ता हो सकता है।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। सरकार और निर्वाचन आयोग की आलोचना करना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन विरोध प्रदर्शन तभी सार्थक होगा, जब वह ठोस तथ्यों, शांतिपूर्ण व्यवहार और स्पष्ट सुधार संबंधी सुझावों पर आधारित हो। इसी प्रकार सत्ता पक्ष को भी विपक्ष की प्रत्येक आपत्ति को राजनीतिक अवसरवाद कहकर खारिज करने के बजाय उसका तथ्यात्मक उत्तर देना चाहिए। लोकतंत्र में संस्थाओं की प्रतिष्ठा केवल उनके अधिकारों से नहीं, बल्कि उनकी निष्पक्षता और जवाबदेही से बनती है। निर्वाचन आयोग को किसी राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात से ऊपर दिखाई देना चाहिए। साथ ही, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वह गंभीर आरोप लगाने के साथ उनके समर्थन में प्रमाण भी प्रस्तुत करें।

सियासी गहमागहमी

अखिर कब थमेगा मग्न में भाजपा नेताओं का अंतर्कलह?

कुछ दिनों पहले मध्यप्रदेश के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव राजधानी भोपाल पहुंचे। यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कोर ग्रुप की एक मीटिंग की। मीटिंग में जिस ढंग से मोहन कैबिनेट के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के प्रति असंतुष्टि जाहिर की उसने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया। यही नहीं अपने ऊपर मंत्रियों को हावी होता देख मोहन यादव ने पल्ला झाड़ते हुए बॉल पहले प्रहलाद पटेल की तरफ फेंकी और उसके बाद उन्होंने गंद उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के ऊपर फेंक दी। यह सब तमाशा देख विप्लव देव विफर गये और उन्होंने सभी नेताओं को दो टूक शब्दों में कहा कि अगर प्रदेश में नेताओं के बीच चली आ रही यह आपसी खींचतान और अंतर्कलह को तुरंत समाप्त नहीं किया गया तो अगले तीन महीने में प्रदेश सरकार की तस्वीर कुछ और हो सकती है। उनके इस बयान के बाद यह चर्चा है कि क्या मग्न में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को भाजपा किनारे कर किसी और को नया मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपिगी।

भूपेश बघेल की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राजनीतिक और कानूनी मुश्किलों को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की संभावित कार्रवाई की अटकलों ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। यदि जांच एजेंसी इस मामले में कोई नया कदम उठाती है, तो इसका असर न केवल बघेल की व्यक्तिगत राजनीतिक स्थिति पर, बल्कि छत्तीसगढ़ की सियासत पर भी देखने को मिल सकता है। भूपेश बघेल के कार्यकाल से जुड़े विभिन्न कथित घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों को लेकर पहले भी जांच एजेंसियां सक्रिय रही हैं। ऐसे मामलों में जांच का आगे बढ़ना स्वाभाविक है, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन की मूल भावना है। दूसरी ओर, कांग्रेस इन कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़कर सवाल उठाती रही है, जबकि जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच करना है। कुल मिलाकर इतना तय है कि इस घटनाक्रम पर छत्तीसगढ़ की राजनीति की नजरें टिकी रहेंगी।

हफ्ते का कार्टून



बेटा! तुम्हारी गलती यही थी कि
तुमने घोषणा करके इमरजेंसी लगाई थी।



ट्वीट-ट्वीट

अजित टाठ की दिल्ली पुलिस खुद तो गुंडागर्दी पर उतर ही आई -
RSS-BJP के असली गुंडे को भी महिलाओं और युवाओं पर
हिसा करने की खुली छूट और बढ़ावा दे रही है।

जैसा मैंने कहा था, Mogambo Modi
और उसकी सरकार गितना दबाएगी, Gen
Z और छात्रों का गुस्सा उतना ही बढ़ेगा।

-राहुल गांधी

काबिल नेता @RahulGandhi



आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ!
नौ दुर्गा जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि
बढ़ी रहे।

-कमलनाथ

छोट काबिल अख्य

@OfficeOfKNath



राजवीरों की बात

संघर्ष, संकल्प और भारतीय राजनीति का एक सशक्त व्यक्तित्व है उमा भारती

समता पाठक/जगत प्रवाह



भारतीय राजनीति के इतिहास में उमा भारती का नाम उन नेताओं में लिया जाता है, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी, प्रखर वक्तृत्व शैली, धार्मिक आस्था और संघर्षशील व्यक्तित्व के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई। मध्यप्रदेश की राजनीति से अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाली उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं में स्थान प्राप्त किया। वे मध्यप्रदेश की मुख्यमंत्री रही और केंद्र सरकार में भी कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उनका राजनीतिक जीवन उपलब्धियों, आंदोलनों, वैचारिक प्रतिबद्धताओं और विवादों से होकर गुजरा है। उमा भारती का जन्म 3 मई 1959 को मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ जिले के डुंडा गांव में हुआ। उनका संबंध एक किसान परिवार से रहा है। बचपन से ही धार्मिक ग्रंथों, आध्यात्मिक विषयों और भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। कम उम्र में ही उन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया तथा प्रवचन देने की प्रतिभा विकसित की। उनकी असाधारण वक्तृत्व क्षमता ने उन्हें किशोरावस्था में ही लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया। धार्मिक प्रवचनों से शुरू हुई उनकी सार्वजनिक यात्रा धीरे-धीरे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की ओर बढ़ी।

उमा भारती का राजनीति में प्रवेश उस दौर में हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी देश में अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत कर रही थी। वे पार्टी के वैचारिक और जनांदोलन संबंधी कार्यक्रमों में सक्रिय हुईं। वर्ष 1984 में उन्होंने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक संघर्ष जारी रखा। वर्ष 1989 में वे मध्यप्रदेश के खजुराहो संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं। इसके बाद उन्होंने कई बार लोकसभा में क्षेत्र और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। अपनी स्पष्टवादिता, आक्रामक भाषण शैली और जनसभाओं में प्रभावशाली उपस्थिति के कारण वे शीघ्र ही राष्ट्रीय राजनीति में चर्चित हो गईं। उमा भारती के राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित अध्याय अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा रहा। इस आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका और प्रभावशाली भाषणों ने उन्हें हिंदुत्व की राजनीति के प्रमुख चेहरों में शामिल कर दिया। दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के बाद उनका नाम राष्ट्रीय राजनीतिक बहसों में प्रमुखता से सामने आया। इस घटना से संबंधित कानूनी और राजनीतिक विवादों ने उनके सार्वजनिक जीवन को भी प्रभावित किया। इसके बावजूद उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों और संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से समर्थकों के बीच अपनी पहचान बनाए रखी।

वर्ष 2003 में मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद उमा भारती राज्य की मुख्यमंत्री बनीं। उनके नेतृत्व में भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अगस्त 2004 तक रहा। हालांकि, कर्नाटक के हुबली में 1994 की एक घटना से जुड़े मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकरण ने उनके राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पैदा किया। इसके बाद भी वे राजनीति में सक्रिय रही और विभिन्न अवसरों पर अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रदर्शन करती रहीं। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उमा भारती ने भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाई और वर्ष 2006 में भारतीय जनशक्ति पार्टी का गठन किया। हालांकि, बाद में वे पुनः भाजपा में शामिल हो गईं। वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश के झांसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर वे संसद पहुंचीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में उन्हें जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। बाद में उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का दायित्व भी संभाला। गंगा की स्वच्छता और नदी पुनर्जीवन से जुड़े विषय उनके केंद्रीय मंत्री के कार्यकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे।

उमा भारती का व्यक्तित्व धार्मिक साधना और राजनीतिक सक्रियता के अनूठे मेल के रूप में देखा जाता है। उनकी पहचान भगवा वस्त्र धारण करने वाली प्रखर वक्ता और स्पष्ट विचार रखने वाली नेता के रूप में रही है। उनके समर्थक उन्हें निर्भीक और संघर्षशील नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं, जबकि उनके राजनीतिक जीवन के कुछ प्रसंगों को लेकर आलोचनाएं भी होती रही हैं। मध्यप्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम राज्य के राजनीतिक इतिहास में विशेष महत्व रखता है। उनका जीवन परिचय इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रभावशाली अभिव्यक्ति और जनसंपर्क की क्षमता किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र तक पहुंचा सकती है। उमा भारती का राजनीतिक सफर भारतीय लोकतंत्र में महिला नेतृत्व, वैचारिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक संघर्ष की एक महत्वपूर्ण गाथा है।

निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में 126 मरीजों को मिला इलाज

-संतोष सिंह कुशवाहा

जगत प्रवाह. ग्वालियर। रतन ज्योति नेत्रालय एवं लाला गोकुल चंद जैसवाल जैन चिकित्सा केन्द्र द्वारा गंज मुरार में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में रतन ज्योति नेत्रालय के डायरेक्टर डॉ. पुरेन्द्र भस्ती के मार्गदर्शन में नेत्र विशेषज्ञों एवं उनकी टीम द्वारा 126 लोगों का नेत्र परीक्षण कर उन्हें परामर्श दिया गया एवं दवा उपलब्ध कराई गई तथा चिन्तित 12 मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन भी किया गया। नेत्र शिविर का

शुभारंभ समाज के वरिष्ठजनों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। लाला गोकुल चंद जैसवाल जैन चिकित्सा केन्द्र के महामंत्री शैलेन्द्र जैन ने बताया कि नेत्र चिकित्सकों की टीम केन्द्र पर प्रतिदिन 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक नेत्र परीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगी। कार्यक्रम में सुदीप जैन, नवीन जैन बैटरी वाले, दिनेश जैन, विजय मामा, सौरभ जैन, नरेंद्र जैन, संजय जैन, शैकी जैन एवं प्रबंध कार्यकारी कमेटी के समस्त पदाधिकारी एवं सभी सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक सौरभ गिरीश जैन का विशेष सहयोग रहा।

राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार और मध्यप्रदेश सरकार पर साधा निशाना

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. बालाघाट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्यप्रदेश के आदिवासी अंचल में पीछित परिवारों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केंद्र और मध्यप्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हुई है, बीमारी और कुपोषण के कारण। जो सपोर्ट सरकार को देनी चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, रोजगार की हो, वो सारा का सारा बंद पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा- "ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के बीच में इनको छोड़ दिया गया है और यहाँ पर हिंदुस्तान की सरकार, मध्यप्रदेश की सरकार है ही नहीं।"

जमीन, मनरेगा और फॉरेस्ट राइट का मुद्दा उठाया

राहुल गांधी ने कहा कि इनकी जमीन का मुद्दा है, मनरेगा का मुद्दा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का मुद्दा है, इनके पट्टे का मुद्दा है। यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दी जा रही। बहुत बच्चे मरे हैं, मुआवजा तक इनको मिला नहीं है। आधे लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूर करनी चाहिए। कम से कम जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो इनका पट्टा है, वो इनको मिलना चाहिए। मनरेगा का आपने नाम बदल दिया, उसको चालू तो कीजिए। और यहाँ पर अस्पताल और स्कूल की जो सुविधा इन लोगों को मिलनी चाहिए, वो दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो, आप 24 घंटा विकास की बात करते हो और 24 घंटा भ्रष्टाचार होता है। मगर जब हमारे आदिवासी भाइयों को जरूरत होती है, तो आप गायब हो जाते हो।

उत्तराखंड का पूर्ण साक्षर राज्य बनना प्रत्येक प्रदेशवासी के लिए गौरव की उपलब्धि : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के देश का छठवां पूर्ण साक्षर राज्य बनने पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि शिक्षकों, विद्यार्थियों, नव-साक्षरों, स्वयंसेवकों और अभियान से जुड़े सभी लोगों की मेहनत एवं सामूहिक सहभागिता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों और दूरस्थ क्षेत्रों वाले उत्तराखंड में पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना प्रदेशवासियों की दृढ़ इच्छाशक्ति और सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कैप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड के पूर्ण साक्षर राज्य बनने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा



संस्थान की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले नव-साक्षरों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और

गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर कांग्रेस ने किया स्मरण

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को स्थानीय रैन बसेरा परिसर में नगर कांग्रेस कमेटी टिमरली द्वारा जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा एवं स्वच्छता के विचारों तथा लाल बहादुर शास्त्री के सादगी, ईमानदारी और देशसेवा के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद पटेल ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक हैं। वहीं नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष जायसवाल ने लाल बहादुर शास्त्री के सादगीपूर्ण जीवन और देश के प्रति उनके समर्पण को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि गंगाराम गुर्जर, ज्योतिरादित्य उपाध्याय, पूर्व पार्षद शहजाद खान, कांग्रेस नेता जितेंद्र सोनकिया, दिनेश तिवारी, चमन, शशिकांत वर्मा, रितु सोलंकी, दीपक जैन, कपिल जाट, सतनारायण राजपूत, संदीप सोलंकी, आदित्य पटेल, राकेश काशीव, नारायण सांखला, सुजेश अग्रवाल, दीपक शर्मा, राजेंद्र नागरे, गिरीश घूरे, अजय राजगुरे, पिंटू चौहान, सुनील मंडलोई, इस्माइल खान, राजू अग्रवाल, सचिन सेठ सहित अनेक कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

सिक्किम के बाद उत्तराखंड देश का छठवां पूर्ण साक्षर राज्य बना है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य को शिक्षा सहित प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के संकल्प को और मजबूती प्रदान करती है। मुख्यमंत्री ने नव-साक्षरों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने यह सिद्ध किया है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और आगे बढ़ने के लिए कभी देर नहीं होती। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविश्वास देने के साथ उसके जीवन में नए अवसरों के द्वार खोलती है। उन्होंने कहा कि साक्षरता का अर्थ अब केवल पढ़ने-लिखने अथवा हस्ताक्षर करने तक सीमित नहीं है। बदलते समय में अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझ, डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता तथा जीवनोपयोगी कौशल भी इसके महत्वपूर्ण अंग हैं।

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च के बीच सरकार का बड़ा कदम!



किशन भावनानी
एडिटर

खपत और उनसे होने वाले कार्बन उत्सर्जन से है। यानों सरकार किसी कंपनी से यह कह रही है कि वह केवल ज्यादा यात्री वाहन बेचने पर ध्यान न दे, बल्कि उसके पूरे वाहन समूह की औसत ईंधन दक्षता भी लगातार बेहतर हो।

सीएफई-3 आखिर है क्या?

यह वाहनों के लिए ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण का सामूहिक नियम है। किसी कंपनी की कुछ यात्री वाहन, कारों ज्यादा ईंधन खर्च करती हैं और कुछ कारें कम ईंधन खर्च करती हैं। सरकार प्रत्येक मॉडल को अलग-अलग एक ही सीमा में बांधने के बजाय कंपनी के पूरे वाहन समूह का औसत देखती है। इसीलिए इसे कॉर्पोरेट औसत कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि समय के साथ कंपनियां ऐसे यात्री वाहन ऐसी कारें बनाएं जो समान दूरी तय करने में कम पेट्रोल या अन्य ईंधन खर्च करें और कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ें। नए सीएफई-3 नियमों में यह व्यवस्था वर्ष-दर-वर्ष अधिक कड़ी होगी, ताकि वाहन उद्योग को अचानक नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से नई तकनीक अपनाने का अवसर मिले।

आम नागरिक के लिए बड़ा मतलब क्या है?

भविष्य की कारों यात्री वाहनों को अधिक ईंधन-कुशल बनाने का दबाव अब वाहन कंपनियों पर बढ़ेगा। नए ढांचे में संदर्भ स्तर पर ईंधन खपत का मानक 2027-28 में 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर से घटकर 2031-32 में 3.3273 लीटर प्रति 100 किलोमीटर किया गया है। यह लगभग 16.7 प्रतिशत सुधार का लक्ष्य है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि ये आंकड़े किसी एक सामान्य कार के वास्तविक सड़क-माइलेज का दावा नहीं हैं। यह कंपनियों के पूरे वाहन समूह की नियामकीय औसत गणना का हिस्सा है। वास्तविक माइलेज कार के मॉडल, वजन, इंजन, सड़क, यातायात और ड्राइविंग शैली के अनुसार अलग हो सकता है।

क्या इसका मतलब है कि पेट्रोल-डीजल कारें यात्री वाहन बंद हो जाएंगी? इसको समझने की करें तो, नहीं। सीएफई-3 का अर्थ यह नहीं है कि 2027 से पेट्रोल या डीजल कारों की बिक्री बंद हो जाएगी। इसका उद्देश्य वाहन कंपनियों को अधिक ईंधन-कुशल और कम-उत्सर्जन वाले वाहनों की ओर ले जाना है। इसके लिए कंपनियों को केवल इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए बाध्य करने के बजाय कई तकनीकों का रास्ते उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन, रेंज बढ़ाने वाली विद्युत तकनीक, प्लग-इन हाइब्रिड, मजबूत हाइब्रिड और फ्लेक्स-फ्यूल वाहन शामिल हैं। इस तरह सरकार ने एक ही तकनीक को अनिवार्य करने के बजाय अलग-अलग तकनीकों को अपनाने की सटीकता से गुंजाइश रखी है।

सुपर क्रेडिट को भी आसान भाषा में समझने की करें तो

कार कंपनियां सिर्फ इंजन बदलकर ही लक्ष्य पूरा नहीं करेंगी। इसको समझने की करें तो, सीएफई-3 में ईंधन बचाने वाली विभिन्न तकनीकों को भी मान्यता दी गई है। इनमें बेहतर कांच, सूर्य की गर्मी को कम करने वाली तकनीक और अधिक दक्ष वातानुकूलन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य की कार में केवल इंजन या बैटरी ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, कार की पूरी बनावट और उसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी ईंधन बचाने में भूमिका निभाएगी। सरकार ने मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीकों की संख्या बढ़ाकर 12 की है और पात्र तकनीकों के माध्यम से उत्सर्जन गणना में निर्धारित लाभ दिया जा सकता है, जिसकी कुल सीमा 9 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर तक है। यात्री वाहनों, कार के वजन का भी नियम में महत्वपूर्ण स्थान है। इसको समझने की करें तो, नए नियमों में कार के वजन को भी ध्यान में रखा गया है। हल्के और भारी वाहनों के लिए लक्ष्य एक जैसा नहीं रखा जाता, क्योंकि भारी वाहन को चलाने में सामान्यतः अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है।



सीएफई-3 की चर्चा में सबसे ज्यादा तकनीकी शब्दों में से एक है सुपर क्रेडिट। इसे सामान्य भाषा में कंपनियों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन अंक समझा जा सकता है। यदि कोई कंपनी इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड या कुछ निर्धारित वैकल्पिक-ईंधन वाली कारें बेचती है, तो सीएफई की गणना में उन्हें सामान्य कारों की तुलना में अतिरिक्त लाभ मिलता है। इसका उद्देश्य कंपनियों को ऐसी स्वच्छ तकनीक वाले वाहनों का उत्पादन और बाजार में विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अंतिम अधिसूचित व्यवस्था में अलग-अलग स्वच्छ वाहन तकनीकों के लिए अलग-अलग गुणक रखे गए हैं। इसलिए इसे यह समझना अधिक सही होगा कि सरकार कंपनियों को स्वच्छ तकनीक अपनाने पर अनुपालन में अतिरिक्त सुविधा दे रही है, न कि ग्राहक को सीधे कोई नकद छूट दे रही है।

इथेनॉल, जैव ईंधन और सीबीजी को भी मिलेगा महत्व को समझने

की करें तो नए ढांचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता कम-कार्बन वाले ईंधनों को मान्यता देना है। इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल, जैव ईंधन और संगीकृत जैव गैस जैसे विकल्पों को कार्बन न्यूट्रैलिटी फैक्टर के माध्यम से सीएफई-3 की गणना में मान्यता देने की व्यवस्था की गई है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि सरकार केवल इलेक्ट्रिक वाहन को ही भविष्य का रास्ता नहीं मान रही, बल्कि भारत में उपलब्ध वैकल्पिक और अपेक्षाकृत कम-कार्बन ईंधनों को भी संक्रमण के हिस्से के रूप में देख रही है। इससे भारत के लिए पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में भी मदद मिल सकती है।

कार कंपनियां सिर्फ इंजन बदलकर ही लक्ष्य पूरा नहीं करेंगी। इसको समझने की करें तो, सीएफई-3 में ईंधन बचाने वाली विभिन्न तकनीकों को भी मान्यता दी गई है। इनमें बेहतर कांच, सूर्य की गर्मी को कम करने वाली तकनीक और अधिक दक्ष वातानुकूलन जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि भविष्य की कार में केवल इंजन या बैटरी ही महत्वपूर्ण नहीं होगी, कार की पूरी बनावट और उसमें इस्तेमाल होने वाली तकनीक भी ईंधन बचाने में भूमिका निभाएगी। सरकार ने मान्यता प्राप्त ईंधन-बचत तकनीकों की संख्या बढ़ाकर 12 की है और पात्र तकनीकों के माध्यम से उत्सर्जन गणना में निर्धारित लाभ दिया जा सकता है, जिसकी कुल सीमा 9 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर तक है। यात्री वाहनों, कार के वजन का भी नियम में महत्वपूर्ण स्थान है। इसको समझने की करें तो, नए नियमों में कार के वजन को भी ध्यान में रखा गया है। हल्के और भारी वाहनों के लिए लक्ष्य एक जैसा नहीं रखा जाता, क्योंकि भारी वाहन को चलाने में सामान्यतः अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसी कारण सीएफई-3 में औसत वाहन वजन से जुड़ी गणना को नए तरीके से व्यवस्थित किया गया है। शुरुआती मसौदे में छोटे और हल्के वाहनों के लिए अलग रियायतों की चर्चा थी, लेकिन

अंतिम व्यवस्था में छोटे पेट्रोल वाहनों के लिए प्रस्तावित विशेष छूट को बरकरार नहीं रखा गया। इसका अर्थ यह है कि केवल छोटी कार होने के आधार पर निर्माता को अलग से आसान रास्ता नहीं मिलेगा, उसे अपने पूरे वाहन समूह के औसत प्रदर्शन को सटीकता से सुधारना होगा।

हम यदि कोई कंपनी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई तो क्या होगा? इसको समझने की करें तो सरकार ने इसके लिए भी लचीली व्यवस्था बनाई है। जो निर्माता निर्धारित लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन करेगा, वह क्रेडिट अर्जित कर सकता है। वहीं किसी निर्माता की कमी होने पर वह उपलब्ध नियमों के अनुसार पिछले क्रेडिट का उपयोग कर सकता है, अन्य निर्माताओं के साथ क्रेडिट का लेन-देन कर सकता है या ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की व्यवस्था के माध्यम से आवश्यक क्रेडिट खरीद सकता है। इसका उद्देश्य कंपनियों को एक झटके में दंडित करने के बजाय उन्हें तकनीकी बदलाव के लिए व्यावहारिक रास्ता देना है, जबकि लक्ष्य पूरा करने की जिम्मेदारी भी बनी रहेगी।

आम नागरिक को आखिर क्या

फायदा होगा? इसको समझने की करें तो, इस पूरे नियम का अंतिम उद्देश्य केवल कार कंपनियों के आंकड़े सुधारना नहीं है। इसका असर लंबे समय में ईंधन खर्च, प्रदूषण, तेल आयात और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। यदि नई कारें औसतन कम ईंधन में समान दूरी तय करने लगती हैं, तो वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए ईंधन की खपत घटाने की संभावना बढ़ेगी। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड विकल्पों की संख्या बढ़ने से उपभोक्ताओं के सामने तकनीक के अधिक विकल्प भी आ सकते हैं। साथ ही कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ शहरों और राजमार्गों पर परिवहन से होने वाले पर्यावरणीय दबाव को कम करने की दिशा में आगे बढ़ना है। हालांकि किसी व्यक्ति की वास्तविक बचत इस बात पर निर्भर करेगी कि वह कौन-सी कार खरीदता है, उसका ईंधन खर्च कितना है, वह कितनी दूरी चलाता है और वाहन की कीमत क्या है।

शारदीय नवरात्रि

आस्था, ऊर्जा और आत्म-उत्थान का महापर्व

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
संस्थापक

: प्रवीण कक्कड़

हवा में एक नई ऊर्जा घुलने लगी है, वातावरण में एक आध्यात्मिक स्पंदन महसूस हो रहा है। यह संकेत है कि शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। नौ दिनों तक चलने वाला दिव्य उत्सव, जो केवल उपवास, पूजा और गरबे तक सीमित नहीं, बल्कि यह हम सभी के लिए एक वार्षिक आमंत्रण है, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ठहरकर, अपने भीतर की उस महाशक्ति को पहचानने का, जो हर चुनौती को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखती है। इस पावन उत्सव पर, आइए इस बार

केवल उपवास ही नहीं, बल्कि अपने भीतर आत्म-जागरण का भी प्रण लें।

यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि हमारे अंदर की वह चेतना है, जो सही समय पर जागृत हो जाए तो असंभव को भी संभव बना देती है। जब हम आदिशक्ति को नमन करते हैं, तो हम उस मूल ऊर्जा को प्रणाम करते हैं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ। आज जब दुनिया अनिश्चितताओं और तनाव से जुझ रही है, तो यह उपासना हमें सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। माँ की शक्ति हमें पोषण भी देती है और अन्याय के विरुद्ध लड़ने का साहस भी। यह हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे भीतर भी सृजन और संहार, दोनों की शक्ति निहित है, सृजन सकारात्मक विचारों का और संहार अपनी नकारात्मकता का।

नौ दिन, नौ संकल्प

आने वाले नवदुर्गा के नौ रूप केवल देवी की मूर्तियाँ नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने वाले नौ शक्तिशाली सूत्र हैं। आइए, इस नवरात्रि में हर दिन एक देवी के गुण को अपने जीवन में उतारने का प्रण लेने की तैयारी करें।

पहले दिन का संकल्प - माँ शैलपुत्री (अडिग विश्वास): पर्वतराज की पुत्री की तरह अपने लक्ष्यों और मूल्यों पर चढ़ाने



की तरह अडिग बनें। प्रण लें कि आने वाले दिनों में छोटी-मोटी बाधाओं से विचलित नहीं होंगे।

दूसरे दिन का संकल्प - माँ ब्रह्मचारिणी (अनुशासन): तप और संयम की देवी हमें सिखाती हैं कि महान चीजें अनुशासन से ही हासिल होती हैं। तय करें कि इस नवरात्रि कोई एक बुरी आदत छोड़ेंगे या एक अच्छी आदत को जीवन में शामिल करेंगे।

तीसरे दिन का संकल्प - माँ चंद्रघंटा (निर्भयता): यह रूप हमें डर पर विजय पाना सिखाता है। उस एक डर का सामना करने के लिए खुद को तैयार करें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है।

चौथे दिन का संकल्प - माँ कूष्मांडा (सकारात्मकता): अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी से प्रेरणा लें। प्रण करें कि इन नौ दिनों में किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन में घर नहीं करने देंगे।

पांचवें दिन का संकल्प - माँ स्कंदमाता (करुणा): मातृत्व की यह देवी हमें प्रेम और करुणा की शक्ति सिखाती है। संकल्प लें कि

आप किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ मदद अवश्य करेंगे।

छठे दिन का संकल्प - माँ कात्यायनी (न्याय): अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाली यह वीरंगना हमें सिखाती है कि चुप रहना भी एक अपराध है। जहाँ भी कुछ गलत देखें, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का साहस जुटाएं।

सातवें दिन का संकल्प - माँ कालरात्रि (अंधकार पर विजय): यह प्रचंड रूप हमें सिखाता है कि सबसे घने अंधकार के बाद ही सुबह होती है। जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे लड़ने के लिए खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं।

आठवें दिन का संकल्प - माँ महागौरी (आत्मशुद्धि): यह शांत और निर्मल रूप आंतरिक शांति का प्रतीक है। प्रण लें कि आप क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष से खुद को दूर रखेंगे और मन को शांत रखने का अभ्यास करेंगे।

नौवें दिन का संकल्प - माँ सिद्धिदात्री (क्षमता पर विश्वास): सभी सिद्धियों को देने वाली माँ हमें हमारी अनंत क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाती हैं। अपने सबसे बड़े सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए खुद को प्रेरित करें।

आराधना का असली अर्थ: उपवास से ऊपर उठकर

याद रखें, नवरात्रि का व्रत केवल अन्न का त्याग नहीं, बल्कि नकारात्मक विचारों, आदतों और शब्दों का त्याग है। असली पूजा थाली सजाना नहीं, किसी की जिंदगी में उम्मीद का दीया जलाना है। जब हम किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, या प्रकृति का सम्मान करते हैं, तभी हम माँ शक्ति की सबसे सच्ची आराधना करते हैं।

उत्सव मनाएं और एक बेहतर इंसान बनें

तो आइए, इस नवरात्रि को केवल एक परंपरा की तरह मनाने की जगह, इसे अपने जीवन का एक "ट्रांसफॉर्मेशनल फेस्टिवल" बनाने का संकल्प लें। यह अवसर है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का, उसे जगाने का और उसे दुनिया के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा में बदलने का। अब से जब आप "जय माता दी" कहें, तो यह सिर्फ एक नारा न हो, बल्कि आपके भीतर की उस दिव्य शक्ति का उद्घोष हो जो आपको और इस दुनिया को और भी खूबसूरत बनाने के लिए तैयार है। यही सच्ची आराधना है और यही आत्म-विजय का असली उत्सव है।

पहाड़ टूट रहे हैं, हमारी नीतियाँ नहीं

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद

देते हैं। लोगों को पर्यटन एवं तीर्थयात्रा का फर्क समझना पड़ेगा। पहाड़ों को समझने और जानने की आवश्यकता है। प्रकृति में ही ईश्वर है। इसके साथ शासन और प्रशासन को इसके लिए नीतियाँ बनाना एवं उन नीतियों को कार्यान्वयन कराने की आवश्यकता है।

पहाड़ दरक रहे हैं, नदियाँ उफान रही हैं, घाटियाँ मलबे से भर चुकी हैं और हम अब भी विकास का वही चरमा पहने हैं, जिसमें केवल सड़कें, होटल और बाँध दिखते हैं, पर टूटते जंगल और उजड़ते गाँव नहीं। यह कोई प्राकृतिक संयोग नहीं, बल्कि हमारी अंधी महत्वाकांक्षाओं और गलत नीतियों का सीधा परिणाम है। 27 जुलाई 1926, नंदा देवी क्षेत्र के निकट

6.5 तीव्रता के भूकंप ने हिमालय की जमीन को झकझोर दिया। 2026 में नेपाल में आसदी हुई। इस सी साल में भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ बादल फटने और हिमस्खलन के रूप में बार बार अपना स्वभाव दिखाया। केदारनाथ त्रासदी, जोशीमठ आपदा आदि घटनाओं के जरिए हमेशा चेतावनी दे रहा है। इन सब का कारण है हमने पहाड़ों की संवेदनशीलता के भीतर अपना हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया है। कभी हरियाली और उल्लास का प्रतीक रही बरसात आज पहाड़ों के लिए अभिशाप बन गई है। उत्तराखंड से हिमाचल, सिक्किम से अरुणाचल और कश्मीर तक बादल फटना, भूस्खलन और नदियों का उफान हर साल सैकड़ों परिवारों को उजाड़ देता है। सवाल यह है कि क्या ये आपदाएँ वाकई प्राकृतिक हैं, या फिर मानव निर्मित? सच्चाई यह है कि पिछले दो दशकों में सड़क चौड़ीकरण, बाँध-सुरंग परियोजनाएँ, होटल-रिसॉर्ट निर्माण और बेरोकटोक खनन ने पहाड़ों की नसों को कमजोर कर दिया है। लाखों वाहनों का धुआँ, बढ़ता पर्यटन और कचरे का बोझ इन नाजुक ढलानों पर मौत का निमंत्रण साबित हो रहा है। पेड़ थे तो पानी सोखते थे; अब नंगे ढलानों पर सीधा मलबा गिरता है। होटल, सड़क और खनन ने पहाड़ों को खोखला कर दिया है।

दुर्भाग्य यह कि इंसान ने केदारनाथ से लेकर हाल की बाढ़ों तक किसी से सबक नहीं लिया। विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरणविदों की चेतावनियाँ कुचल दी गईं। परिणामस्वरूप, खेती और पशुपालन संकट में हैं, पलायन तेज हो रहा है और आपदा का बोझ सबसे अधिक बुजुर्गों और महिलाओं पर पड़ रहा है। प्रकृति हमें उसी जगह चोट पहुँचाती है जहाँ हम लालची होते हैं। होटल बह जाते हैं, सड़कें दरक जाती हैं, बाँध टूट जाते हैं। बारिश की पहली बौछार अब आपदा बन जाती है। जलवायु परिवर्तन ने इस संकट को और विकराल बना दिया है।

सरकार राहत बाँटती है, पर असली सवाल दब जाता है बार-बार आपदा क्यों? सच यही है कि हर पहाड़, घाटी और नदी की एक सीमा है, पर हमने उन्हें असीम समझकर लाद दिया। पहाड़ पत्थर के हैं, पर संवेदनहीन नहीं। उनकी भी साँस और रक्त है जो नदियों में बहता है। जब यह घुटता है, तो विनाश बनकर लौटता है।

अब भी वक्त है कि हम प्रकृति को साझेदार मानें, वरना इतिहास यही लिखेगा कि इंसान का विनाश उसी ने खुद किया। यह समय है कि हम "विकास" की परिभाषा दोबारा लिखें। असली विकास वही है जो पहाड़ों की सहनशीलता का सम्मान करे, उनकी संरचना और स्थानीय समुदायों को बचाए। "सस्टेनेबल डेवलपमेंट" नारा नहीं, बल्कि नीति और व्यवहार बनना चाहिए।

आज की तबाही हमारे अहंकार और अंधे विकास का परिणाम है। सरकार ही नहीं, समाज और नागरिक भी इसके दोषी हैं। जब हम पहाड़ों को पर्यटन और उपभोग की वस्तु बना देते हैं। पहाड़ पूजा की वस्तु नहीं, बल्कि जीवित परिसंस्थितिकी हैं, जिनसे संतुलन बनाकर ही हम जी सकते हैं। हिमालय अस्थिर हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियाँ अस्तित्व में ही नहीं हैं, और इसका असर मैदानों तक पहुँचेगा। यह संकट पूरे भारत का है। हमें मानना होगा कि पहाड़ सीमित और संवेदनशील हैं। उनका सम्मान ही हमारी सुरक्षा है। समाधान स्पष्ट है पहाड़ों की वहन-क्षमता का वैज्ञानिक आकलन, स्थानीय समुदाय की भागीदारी, नियंत्रित पर्यटन, और वनीकरण व जल-संरक्षण पर बल। पहाड़ हमें वहाँ से जाने को नहीं कहते बल्कि वे हमें उनके साथ अपना संबंध बदलने की चेतावनी देते हैं। पहाड़ हमें शायद सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही देता है कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका सहभागी है।



Chhattisgarh
Business Made
Easy



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

छत्तीसगढ़: उद्योगों से भविष्य का निर्माण

नए क्षेत्रों में तेज़ विस्तार | निवेश धरातल पर | युवाओं के लिए रोजगार

₹ 8.23 लाख करोड़

अब तक की निवेश प्रतिबद्धताएँ

1.5 लाख+

अपेक्षित रोजगार

50% थ्रस्ट

सेक्टर परियोजनाएँ

नए क्षेत्रों में प्रगति

- नवा रायपुर में भारत का पहला एआई डेटा सेंटर
- मध्य भारत का सबसे बड़ा फार्मा पार्क
- नवा रायपुर में राज्य का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट
- भारत के सबसे बड़े पेट फूड ब्रांड का विनिर्माण केंद्र
- नवा रायपुर में गारमेंट पार्क, वस्त्र उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन



हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

[/ChhattisgarhCMO](#)
[/DPRChhattisgarh](#)
www.dprcg.gov.in



छत्तीसगढ़ की पहचान अब केवल उसकी खनिज संपदा से नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण, वास्तविक परियोजनाओं, नए रोजगार और विविध आधुनिक अर्थव्यवस्था से भी है।

- विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़